E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2023; 5(2): 57-60
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 18-06-2023
Accepted: 24-07-2023

सरिता यादव
पीएच. डी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
सरिता यादव
पीएच. डी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर, राजस्थान, भारत

भारत में समावेशी एवं सुलभ न्याय में ग्राम न्यायालयों की भूमिका

सरिता यादव

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i2a.411

सारांश
हमारे देश का पहला ग्राम न्यायालय 27 नवम्बर, 2010 को राजस्थान के बस्सी गांव में स्थापित किया गया था। ग्राम न्यायालय की स्थापना भारतीय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट पर आधारित थी। यह रिपोर्ट भारत के विधि मंत्रालय को भेजी गई थी और इस रिपोर्ट पर भारत के विधि मंत्रालय ने विचार किया और इस संबंध में भारतीय संसद द्वारा ग्राम न्यायालय विधेयक पारित किया गया और उसके बाद "ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008" अस्तित्व में आया। भारतीय संसद द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय न्यायपालिका के कंधों से लंबित मामलों का बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। संसद और उच्च न्यायपालिका के सभी सदस्यों की आम राय थी कि 'ग्राम न्यायालय' आधुनिक भारत में न्याय का एक नया मॉडल है जो गांव स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करेगा और न्याय प्रशासन की स्थापना में भी भूमिका निभाएगा। विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में विधि न्यायाधीशों की गुणवत्ता और 'ग्राम न्यायालय' के अधिकार क्षेत्र के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए थे और साथ ही इस न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों के प्रकारों के बारे में भी बताया गया था। इस रिपोर्ट में एक अलग न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी जिसका नाम पंचायती राज न्यायिक प्राधिकरण था। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के विधि मंत्रालय को दी गई आपराधिक और सिविल की अलग-अलग शक्तियों की सिफारिश पर विचार नहीं किया गया और कुछ परिवर्तनों के साथ संसद द्वारा 'ग्राम न्यायालय' अधिनियम, 2008 पारित किया गया, जिसमें आपराधिक और सिविल मामलों में अधिकारिता और शक्ति तथा प्रक्रिया, अपील प्रावधान जैसे विभिन्न प्रावधान शामिल हैं और आशा है कि 'ग्राम न्यायालय' राजस्थान राज्य में लंबित मामलों की संख्या को शीघ्रता से कम करने में सफल होगा।

कुटशब्दः सहभागी न्याय, विधि आयोग, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

प्रस्तावना
ग्राम न्यायालयों के निर्माण का सुझाव सबसे पहले भारत के विधि आयोग ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में दिया था। ग्राम न्यायालयों पर भारत के विधि आयोग की 1986 की रिपोर्ट का त्वरित अवलोकन न्याय पंचायत मॉडल से दूर जाने की

उनकी घोषित इच्छा को दर्शाता है। रिपोर्ट का पहला प्रमुख जोर भागीदारी न्याय के विचार की ओर था। विधि आयोग ने भारतीय कानूनी प्रणाली की विदेशी प्रकृति को इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक के रूप में पहचाना। इसके बाद विधि आयोग ने विवादों का निपटारा करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय परिस्थितियों और संस्कृति के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसे प्राप्त करने के लिए आयोग ने तीन सदस्यीय पैनल द्वारा संचालित ग्रामीण न्यायालय के मॉडल पर सहमति व्यक्त की। इस पैनल का नेतृत्व न्यायिक रूप से प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा किया जाना था जिसके साथ दो सामान्य न्यायाधीश भी होने थे। जबकि न्यायिक अधिकारी का चयन प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए न्यायाधीशों के कैडर से किया जाना था सामान्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिलकर बने पैनल द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जानी थी। इसलिए न्याय पंचायतों के विपरीत ग्राम न्यायालय में लोकतांत्रिक चुनाव का कोई घटक नहीं था। फिर भी विधि आयोग सामान्य निर्णय के लाभों के बारे में आश्वस्त प्रतीत हुआ। विधि आयोग ने प्रस्तावित ग्राम न्यायालयों के लिए कोई वित्तीय सीमा निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सिविल मामलों में केवल उन विषय-वस्तुओं की सूची निर्दिष्ट की जिन पर ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। सामान्यतः यह न्याय पंचायतों को दिए गए क्षेत्राधिकार से अधिक विस्तृत था। विधि आयोग भी ग्राम न्यायालयों को आपराधिक मामलों में व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करने के पक्ष में था जैसा कि ग्राम न्यायालय में न्यायाधीशों के पैनल में प्रस्तावित न्यायिक सदस्य की उपस्थिति के कारण न्याय पंचायतों के मामले में पहले था। इसके अलावा विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बाहर करके सिविल मामलों में सरल प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा। आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता अभी भी लागू होगी। वकीलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से ग्राम न्यायालय मोबाइल होंगे इस अर्थ में कि उन्हें व्यक्तिगत विवादों के स्थलों की यात्रा करनी होगी। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करने की समस्याओं का समाधान करना था।

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाई गई कुछ विशेषताएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए ग्राम न्यायालयों को 'मोबाइल' रहना है और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गांवों का समय-समय पर दौरा करना है। हालांकि विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। ''सहभागी न्याय का विचार अनुपस्थित है जो विधि आयोग के मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। संक्षेप में 2008 के अधिनियम में न्याय पंचायत मॉडल के साथ-साथ 1986 की विधि आयोग की रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: न्याय पंचायतों और 1986 की विधि आयोग की रिपोर्ट ने ग्रामीण विवादों में न्यायधीशों की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन व्यक्तियों को स्थानीय रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में अधिक जानकारी थी। इसके विपरीत, 2008 का अधिनियम यह स्थापित करता है कि प्रत्येक ग्राम न्यायालय का नेतृत्व एक न्यायाधिकारी करेगा जिसके पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कम से कम न्यायाधिकारी के पास कानून की डिग्री होनी चाहिए। यह पेशेवर न्यायाधीशों द्वारा न्यायनिर्णयन के पक्ष में आम लोगों के निर्णय के वादे को अस्वीकार करने जैसा प्रतीत होता है।

ग्राम न्यायालयों की कार्यप्रणाली

न्यायाधीश वकील और प्रक्रियाएँ पेशेवर न्याय वितरण पर जोर जैसा कि पहले चर्चा की गई है ग्राम न्यायालय अधिनियम पेशेवर रूप से योग्य न्यायाधीशों के अपने प्रावधान और कानूनी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में न्याय पंचायत मॉडल से काफी अलग है। अधिनियम की धारा 6 में यह अनिवार्य किया गया है कि न्यायाधिकारी के पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान योग्यताएँ होनी चाहिए। संभवतः इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि इसमें औपचारिक न्यायिक संरचना से बाहर के व्यक्ति शामिल हैं लेकिन उनके पास आवश्यक योग्यताएँ हैं: जैसे अभ्यासरत वकील सेवानिवृत्त न्यायाधीश इत्यादि। हालाँकि हमने जिन ग्राम न्यायालयों का अवलोकन किया उनमें अपने-अपने राज्यों में न्यायपालिका के मौजूदा सदस्य कार्यरत थे। इसके अलावा ये ग्राम न्यायालय वास्तव में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पहले से ही मौजूद न्यायालय थे जिन्हें अतिरिक्त रूप से ग्राम न्यायालय नाम दिया गया था। इसलिए सप्ताह या महीने के अधिकांश दिनों में ये जिला या तालुका न्यायालय परिसर में सामान्य न्यायालय कक्ष थे। कुछ निर्दिष्ट दिनों में वे बाहर जाते थे और गाँव का दौरा करते थे। इस तरह उनका ग्राम न्यायालय कार्य पूरा होता था। दूसरा तीन में से कम से कम दो ग्राम न्यायालयों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ अपने मामलों की सूची साझा की। इसका मतलब यह है कि 'न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में अपनी समानांतर क्षमता में उन्हीं मामलों की सुनवाई करते थे। तीनों मामलों में उनकी सूची मुख्य रूप से दीवानी मामलों की बजाय आपराधिक मामलों की थी। हम इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं। कम से कम इन आधारों पर ग्राम न्यायालय का शीर्षक वास्तव में एक नई संस्था के चिह्न की तुलना में नाममात्र की श्रेणी अधिक प्रतीत होता है।

ग्राम न्यायालय की प्रमुख भूमिका

- 'ग्राम न्यायालय' जमीनी स्तर पर मुद्दों को निपटाने के लिए एक त्वरित तंत्र है।
- 'ग्राम न्यायालय' ने सामान्य न्यायालयों के कंधों से लंबित मामलों का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 'ग्राम न्यायालय' द्वारा वादियों को घर-द्वार पर न्याय प्रदान किया गया है।
- 'ग्राम न्यायालय' द्वारा न केवल स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा की जाती है बल्कि कुशलतापूर्वक न्याय भी प्रदान किया जाता है।
- 'ग्राम न्यायालय' प्रणाली ग्रामीणों के लिए कुछ प्रकार के शिक्षाप्रद मूल्य प्रदान करती है।
- 'ग्राम न्यायालय' ग्राम स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करने का सक्रिय स्रोत है।
- 'ग्राम न्यायालय' में सभी विवादों का निपटारा 'पंच-परमेश्वर' की अवधारणा द्वारा किया जाता है जो प्रश्नावली से प्राप्त विचारों से सिद्ध होता है।
- ग्राम न्यायालय का संचालन पुराने न्यायिक परीक्षण की तुलना में मुकदमेबाजी के लिए सस्ता है।

निष्कर्ष

ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को न्यायिक संस्थाओं तक ग्राम स्तर की पहुँच प्रदान करना है। हालाँकि वे अपनी संरचना और कार्यप्रणाली दोनों में ही बहुत अलग हैं। वे किसी भी बिंदु पर विवाद समाधान के एक विशिष्ट स्थानीयकृत रूप की पेशकश करने का दावा नहीं करते हैं। अधिकांश भाग के लिए वे विरोधात्मक न्यायनिर्णयन के विचार पर आधारित न्याय वितरण के एक पेशेवर मॉडल को अपनाते हैं। इस संबंध में वे किसी भी स्वदेशी या पारंपरिक संस्थाओं वास्तविक या आदर्श की तुलना में देश

में 'औपचारिक' न्यायालयों के बहुत करीब हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली की व्यापक कहानी में न्याय पंचायतों से ग्राम न्यायालयों की ओर कदम संभवतः विवाद समाधान के पारंपरिक मॉडल पर लौटने के राज्य के प्रयासों के निर्णायक अंत और औपचारिक न्यायालय प्रणाली के धीमे और स्थिर विस्तार पर आधारित मॉडल की ओर कदम को दर्शाता है।

संदर्भ

1. ड्रमंड जे.जी. भारत में पंचायतें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन 1937
2. गैलेंटर मार्क. आधुनिक भारत में कानून और समाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली 1997
3. गुरुस्वामी मेनका सिंह आदित्य. अन्याय तक पहुँच: ग्राम न्यायालय अधिनियम आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक।
4. ट्राइब लॉरेंस एच. संवैधानिक विकल्प यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली
5. भारतीय विधि आयोग ग्राम न्यायालय पर एक सौ चौदहवीं रिपोर्ट।
6. कृष्णास्वामी सुधीर ग्राम न्यायालय अनौपचारिक न्याय के खतरे।
7. विधायी संक्षिप्त ग्राम न्यायालय विधेयक 2007 पीआरएस विधायी अनुसंधान केंद्र।